

LOK SABHA

Thursday, July 25 1968/Sravana 3,
1890 (SAKA)

The Lok Sabha met at Eleven of
the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair.]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छोटे समाचार पत्र

†

- *91. श्री श्रीकार सिंह :
श्री अनन्तराव पाटिल :
श्री शरदानन्द :
श्री घटल बिहारी वाजपेयी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री श्रीकारलाल बोहरा :

क्या समाचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक की दरों में हाल में की गई वृद्धि में समाचारपत्रों को, विशेष रूप से 50 ग्राम ग्रथवा इसमें कम वजन वाले समाचारपत्रों को, काफी नुकसान हुआ है;

(ख) क्या छोटे समाचारपत्रों को डाक की दरों में विशेष रियायत देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ध्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Government have no specific information.

(b) No further concessions are contemplated. The present rates for regd. newspapers are already concessional.

(c) Does not arise.

श्री श्रीकार सिंह : आज जो छोटे समाचार पत्र हैं उनके द्वारा ही गाँवों में लोकतंत्र की भावनायें प्राप्ती हैं, तो क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उनको कोई विशेष सुविधायें देंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : छोटे समाचार-पत्र गाँवों और छोटे शहरों में जाते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसके लिये मैं उनको बढ़ाई देता हूँ। लेकिन इस महकमे की मुश्किल यह है कि पोस्टल सर्विस में रजिस्टर्ड न्यूजपेपर्स को मेत्रने में महकमे को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। रेट बढ़ाने के बाद भी हम उसको 50 फीसदी सब्सिडी देते हैं। शायद आपको मालूम होगा कि . . .

SHRI LOBO PRABHU: Please give the figures.

SHRI I. K. GUJRAL: Yes. The average cost per packet transmission is 14.76 p.

SHRI LOBO PRABHU: That is an old figure.

SHRI I. K. GUJRAL: No. The cost of transmission is same. Now, the revenue is 6.05 p. In this, the element of subsidy is about 59 per cent. Therefore, even with the increased rate, our total loss on this type of service will be Rs. 196 lakhs. So, the Department really finds it difficult, much as it would wish to help small newspapers, to give more concessions.

श्री श्रीकार सिंह : क्या मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से डाक दर बढ़ गई है तब से छोटे समाचार-पत्रों की संख्या कितनी घट गई है ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह मेरी नोटिस में नहीं क्योंकि इस महकमे का इससे सम्बन्ध नहीं है ।

SHRI ANANTRAO PATIL: I am very much pained to hear from the hon. Minister that already concessions have been given to newspapers. Before I put my question, you may kindly allow me to explain the position as to what has happened after the increase in postal rates.

MR. SPEAKER: You want to educate the Minister.

SHRI ANANTRAO PATIL: Before the introduction of the decimal coinage, in one rupee, 64 copies could be sent by post whereas now hardly 10 copies can be sent by post. After this increase the newspapers are hard hit, specially the small district newspapers and the medium-sized provincial newspapers because they are largely dependent for their circulation on postal subscribers. The Finance Minister, last year, allowed concessions and kept 2 p. per copy upto 60 grams. This promise was kept but his generosity lasted only for 8 months. This year, he increased the rate by 5 p. upto 50 grams. Under these conditions, I would like to know from the hon. Minister what made the Finance Minister to change his mind and to increase the postage for which he says he has already given concessions. My second question will be as to whether the Government wants the small newspapers to die and the big papers to grow more because the newspapers which have got more weight...

MR. SPEAKER: You have asked the question.

SHRI I. K. GUJRAL: So far as his second question is concerned...

SHRI RAJARAM: He did not complete it. How are you replying?

AN HON. MEMBER: It is for the Speaker to say.

SHRI I. K. GUJRAL: For the information of the hon. Member, his second question was whether the Government wishes the small newspapers to die....

SHRI RAJARAM: He did not complete the question.

MR. SPEAKER: Order. order.

SHRI I. K. GUJRAL: So far as the first part of the question is concerned, while I repeat my sympathy with the small newspapers and I very much appreciate the role they are playing in the national life, what I would like to submit to the hon. Member's consideration is that the hon. Finance Minister here was basically motivated by the recommendations of the Tariff Enquiry Committee. The Tariff Enquiry Committee went into the details of the subsidy element and felt that, although the various other services could bear their cost, in the case of newspapers we could give subsidy to a maximum of 66-2/3 per cent. The subsidy that we are giving is about 59 per cent even now. While I do appreciate the difficulty, the hon. Member may kindly appreciate that for transmission of 224 million newspaper packets, we are subsidising even this year to the tune of Rs. 195 lakhs. This is not a small subsidy, particularly because our total income from this service is estimated to be 135.2 lakhs against a costs of 330.62 lakhs.

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : डाक दर बढ़ने के पहले एक छोटा समाचार-पत्र 2 पैसे में जाता था और अब 5 पैसे में जाता है अर्थात् डार्डिनी बढ़ोतरी हो गई है । जहाँ तक मंत्रो महोदय का प्रश्न है ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि डाक विभाग के सदस्य या हर विभाग सिलक रिलायेंट होना चाहिये । नहीं तो अगर छोटे पैकेट पर नुकसान भी होता है तो बड़े पैकेट पर फायदा हो सकता है, और अगर पूरी पारसल सर्विस पर नुकसान होता है तो किसी और सर्विस में

फायदा होता हीगा, और अगर किसी सर्विस में फायदा नहा होता तो पोस्टल सर्विस तो एक यूटिलिटी डिपार्टमेंट है। मंत्री महोदय समाजवाद का नारा लगाते हैं तो क्या वह इसके लिये तैयार हैं कि दो चार मेम्बर पार्लियामेंट की एक कमेटी बना दी जाय जो और भी दृष्टिकोणों से इस पर विचार करे ?

श्री इ० कु० गुजराल : हम सिर्फ नारा ही नहीं लगाते हैं, हम सोशलजिज्म लाना भी चाहते हैं। सिर्फ इस बात का मवाल नहीं है . . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I shall request the Minister to repeat it.

MR. SPEAKER: Not necessary; it is as good as having said hundred times.

SHRI I. K. GUJRAL: For the benefit of my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, who has neither contributed to, nor understood, socialism, I would say this. I would like him to understand that we contribute to socialism.

Therefore, the basic thing that I would like to say is that socialism does not mean this that services should run at a loss. Where there is a service rendered, it is for the Parliament to decide how they would like to meet the expenditure. Our expenditure in postal services last year was to the tune of Rs. 88.43 crores, and our revenue was about Rs. 72.46 crores. So, there was a net loss in the postal services to the tune of Rs. 16 crores, last year necessitating an increase in tariffs so that the postal branch breaks even this year. It is for this august body to decide whether they would like us to raise some funds from the services that we run or they would give us from other things. Naturally this has to be made up.

So far as newspapers are concerned, I repeat it is a highly subsidised service. It is for the members of this august body to decide what should be done. The Budget was passed

here and we are only carrying out what the Parliament has decided.

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : कमेटी के बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया ?

श्री श्रीकंठर लाल बोहरा : समाचार-पत्र डिमाक्रेसी में बहुत बड़ा रोल रखते हैं और चौथी स्टेट माने जाते हैं। हमारी प्रधान मंत्री जब इन्फार्मेशन और ब्राडकारिंग मिनिस्टर थीं तब उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ कहा था कि छोटे समाचार-पत्रों और भारतीय भाषाओं के पत्रों को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जायेगा। लेकिन बड़े ग्रफसोस की बात है कि भारतीय भाषाओं और छोटे समाचार-पत्रों के ऊपर पिछले दिनों बजट में जो कुठाराघात किया गया है उसके बारे में मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है। मेरा प्रश्न केन्द्रीय सरकार में संचार मंत्रालय के द्वारा है। यह प्रश्न सूचना मंत्रालय, संचार मंत्रालय और फाइनेन्स मिनिस्ट्री से सम्बन्ध रखता है। बड़े बड़े पत्रों के लिये अगर आप पोस्टल रेट्स बढ़ा दें तो वे तो एफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन छोटे जो समाचार-पत्र हैं वे इस कारण से एकदम सभाप्त हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप जैसे पहले था कि माठ ग्राम पर दो पैसे लगते थे, वैसे अब भी इन छोटे समाचारपत्रों के लिये नहीं कर सकते हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस वक्त हम रिवाइज करने की स्थिति में नहीं हैं। बजट यहाँ पास किया गया था और जब कभी पार्लियामेंट रिवाइज करना चाहेगी, कर सकती है। यह सुप्रीम बाडी है और यह अगर चाह तो इसको भी कर सकती है।

श्री कंठर लाल गुप्त : आप प्रोपोजल नाइये, हम पास कर देंगे।

श्री शिंकरे : ऐसे बहुत से पेपर हैं जिनकी कीमत पाँच छः पैसे होती है और उनका जो सब्सिडिशन है वह ज्यादातर डाई पोस्ट ही होता है, बाहर ही उनको भेजा जाता है। अब पाँच पैसे उस सबवार को भेजने में खर्च करने पड़ जाते हैं। यह तो उसी कहावत

को चरितार्थ करता है कि मियाँ बिल्ला भर, दाढ़ो हाथ भर। पाँच पैसे का पेपर और पाँच पैसे उसको भेजने का खर्च। इसका परिणाम यह होता है कि ये जो छोटे पेपर हैं ये लास में चलते हैं। इस वास्ते मैं जानना चाहता हूँ कि जो छोटे पेपर हैं उनको कोई सुविधा देने की सरकार कृपा करेगी ताकि वे भी जारी रह सकें, वे भी अपने सर्क्युलेशन को बढ़ा सकें और जो उनको धक्का पहुंचा है, उससे उनको बचाया जा सके? गोआ में हमने देखा है कि बहुत स डेजो हैं जिनकी सर्क्युलेशन पोस्ट से होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे जो पेपर हैं उनको कोई सुविधा प्रदान करने के लिये क्या सरकार तैयार है ?

SHRI I. K. GUJRAL: It is a suggestion for action.

MR. SPEAKER: Every suggestion is in the form of a speech.

SHRI LOBO PRABHU: The hon. Minister has stated that he has no information about the decrease in the number of small newspapers. As a publisher of two papers, I may inform him that one paper has decreased 50 per cent, and instead of being a weekly it is now a fortnightly. Another paper which was a monthly has become a six-weekly. The point that I wish to make is that instead of the revenues of Government benefiting by this higher rate, they are likely to lose, because no paper can afford to pay these rates, considering that the readers are poor and these are mostly vernacular papers meant for them.

My second question is this. . .

MR. SPEAKER: He has not put any question at all but only given information.

SHRI LOBO PRABHU: I supplied information because the hon. Minister had said that he had no information.

My first question is this. Can the hon. Minister deny that a committee

appointed by Government themselves, namely the committee on small newspapers had recommended that the rate of postage for all papers weighing less than 50 gm. should be one paisa? Government has ignored that recommendation and that concession to be made by this Finance Minister? Why have they ignored it?

My second question is this, how do Government claim that it costs them 14.5 paise per transmission? Have they related it to the weight of the papers or only to the total number of newspapers? How is this calculation made? If their calculations are as good as that, are they willing to put them on the Table of the House? I am asking for this because I dispute their calculation.

SHRI I. K. GUJRAL: Taking the dispute part of the hon. Member's question first, I would say that all this analysis has been made in the Tariff Committee's report, and if the hon. Member will see it with care he will see the analysis made there. So far as our calculating the cost is concerned, it is calculated on the basis of the average number of packets that are transmitted and the total cost that we incur on them. The hon. Member will also appreciate that we have got a huge volume of traffic, namely 224 million packets a year, and it is very difficult for us to break it up, because the cost of breaking it up would be considerably higher. So far as the information given by the hon. Member regarding closing down of the paper is concerned I have noted it with regret, but I would also suggest to him that if he starts selling or distributing his paper freely, he will make some loss.

SHRI LOBO PRABHU: I have not asked for help from him. This is no reply to my question.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: The hon. Minister has quoted certain statistics about the loss. May I know whether he has got any statistics of

the total volume of the news packets received, and whether it is a fact that on account of the increase in the tariff, the volume of the newspaper packets has been reduced considerably and that accounts for the loss in the revenues of Government?

SHRI I. K. GUJRAL: My hon. friends may note that the postal service is one such service where the more we transmit the more we lose. As the traffic expands, the losses go up. It is not as if when the traffic goes up the profit goes up. For, this is a labour-intensive activity. Therefore, the more the number of packets transmitted, the greater is the amount of losses and the losses mount up.

SHRI ANIRUDHAN: May I know whether the hon. Minister is aware that most of the newspapers, especially the language newspapers and the small, smaller and even medium newspapers, have ceased publication within the last decade because of their financial difficulties. For example, even our Law Minister Shri Govinda Menon was having a paper called *Deenabandhu*, and some of the other Chief Ministers in our State having their influence, published their newspapers there. I think that not less than one thousand papers have ceased publication there recently. As a publisher myself, I can understand the difficulties of a publication. I used to affix only some 2 nP. stamp on an ordinary paper which may have only four pages, but now I have to affix 6 nP stamp on the same paper. In view of the fact that small newspapers have only four pages and they are being published regularly and they used to affix only 2 nP stamps on them some months back before the renewal, and thereby they have to affix 300 per cent more than what they used to do before, will Government consider this question of reducing the rates? In this connection, I would like to draw the attention of the House to what Gladstone said once in the British Parliament, when they introduced tax on paper,

'Do not tax knowledge'. In the same way, I may also say that let not Government try to tax knowledge and try to suppress the small newspapers and the smaller newspapers. So, Government may kindly reconsider the position.

MR. SPEAKER: Shri Rane.

SHRI ANIRUDHAN: My question has not been answered.

MR. SPEAKER: It is a suggestion which he has made. So, no answer is needed. The hon. Member has made an appeal to the Government to reconsider the position. That is not a question.

SHRI RANE: May I know whether the Ministry has received representations from various States from associations of the small newspapers and if so, how many?

SHRI I. K. GUJRAL: Some representations have been received.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्दी में एक पुरानी कहावत है अंधेर नगरी बेबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा । छोटे और बड़े अखबारों को एक ही तराजू में रख कर सरकार इस कहावत को चरितार्थ करती हुई मालूम होती है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर छोटे पत्रों पर जो बजट के अन्दर भार डाला गया है उसको एकदम कम करना सम्भव न हो तो क्या मंत्री महाादय कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे छोटे पत्रों को राहत मिल सके और क्या इस बारे में गम्भीरता से विचार करने का आग्रवासन देंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : गम्भीरता से विचार करने का मैं आग्रवासन दे सकता हूँ ।

श्री एलर्बर् सिह : मैं मैम्बर आफ पार्लिमेंट के मफाद की बात पूछना चाहता हूँ । बेचारे बहुत से मैम्बर पार्लियामेन्ट ऐसे हैं जो अपने छोटे छोटे अखबारों पर चलाते हैं, बहुत से बुलेटिन चलाते हैं, बहुत सी कारेसपोण्डेंस करते

हैं, खतोकिताबत करते हैं। यह सब पब्लिक के इंस्ट्रुमेंट को मद्देनजर रख कर करते हैं। बांबेभूद कम तनख्वाह होने के ये दुगुना और तिगुना एक्सपेंस पोस्टल रेट्स पर लगाते हैं। क्या कोई ऐसी प्रोपोजल सरकार के दिमाग में है कि ऐसे जो पब्लिक की सर्विस के काम हैं, जनता की सर्विस के काम हैं, देश की सर्विस के काम हैं और जो पार्लियमेंट के मेम्बर करते हैं उनसे उनकी जो खतोकिताबत होती है, उनके जो अखबार होते हैं, उनके जो बुलेटिन होते हैं, उस पर यह रिड्यूस् रेट्स लागू किये जायें ?

श्री इ० कु गुजराल : अध्यक्ष महोदय, जो शुश्रुकल आनरेबल मेम्बर ने बयान की है उसको देखने के लिये आपने भी एक कमेटी बनाई है और मेरा खयाल है कि वह कमेटी आपके सामने अपनी सिफारिशें रखेगी।

SHRI SEZHIYAN: The hon. Minister gave the figures of 225 million packages and Rs. 196 lakhs loss. Nobody wants to increase the loss on this when they increase the rates, they should see that it does not affect the small newspapers. I would like to tell him that if small newspapers selling at 10P or 7P have to affix 5P stamp, it comes to 50 per cent of the price. If a newspaper is sold at 30 or 40 P, this increase will not amount too much. So will the Minister consider the matter and see that there is some relation between the postage rate and the selling price of the newspaper?

SHRI I. K. GUJRAL: I have already promised that we will give due consideration to the matter.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मिनिस्टर साहब ने कभी जो आंकड़े दिये हैं, मैं उनको टोटली ब्रुत करार देता हूँ क्योंकि मुझे छोटे और बड़े अखबारों का अन्तर है और मैं उनकी ऐसोसियेशंस का अधिकारी भी हूँ। जो कुछ उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं इतना ही

कह सकता हूँ कि वह अखबारों का खर्च नहीं है बल्कि वह पैकेटों और दूसरी बड़ी-बड़ी चीजों पर घाटा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस सिलसिले में पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी बनायेंगे, ताकि इस सारे मामले को उसके सामने रख कर उस पर दोबारा गौर किया जाये।

श्री इ० कु गुजराल : सवाल यह नहीं है कि हम रेट फिक्स कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 100 ग्राम के न्यूजपेपर के हम 5 पैसे लेते हैं और बुक पैकेट के 35 पैसे लेते हैं। इसलिये कन्फ्यूजन हमारे आंकड़ों में नहीं है आनरेबल मेम्बर के इनको समझने में है।

SHRI RANGA: Should newspapers be turned into book packets?

SHRI I. K. GUJRAL: That is more expensive.

SHRI HEM BARUA: Is it a fact that the Small Newspapers' Association has submitted a memorandum to Government requesting them to revise the postal rates so that the small newspapers might exist and live? Since the revenue receipt is not going to be of a large order due to the increased rates, what is the response of Government to this memorandum?

SHRI RANGA: All the members are now submitting a memorandum.

SHRI I. K. GUJRAL: We examined it at that time and then when the present formulation came before you, this difficulty was pointed out. As I have said, we have sensed the feeling of the House and we will examine it.

श्री जिव नारायण : मंत्री महोदय यह जानते ही हैं कि छोटे-छोटे अखबार पाँवों में जाते हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि जो लोच अखबार पढ़ते हैं, क्या सरकार ने उनसे भी पूछा है। अखबारों का दाम कितना बढ़ गया है। जब दोपैसे लगते थे तब अखबारों का क्या दाम था और आज क्या दाम है ?

MR. SPEAKER: Next question. Before that, I would like to say that every supplementary is tending to become a small speech. Once in a way in order to elucidate a point, it may perhaps be necessary to do so. But not in the case of every supplementary. We have already spent 25 minutes on this question alone.

SHRI HEM BARUA: Not every supplementary is long.

SHRI PILOO MODY: Every supplementary is becoming a speech and every answer is becoming silence.

Delhi State Co-operative Bank

*92. **SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH:** Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a former employee of the Delhi State Cooperative Bank has been arrested on the 15th June, 1968 for alleged cheating of the Bank;

(b) if so, whether some more arrests have been made in this case and if so, the number of officials involved therein; and

(c) the progress so far made in the investigation of the case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) Yes Sir.

(b) Yes, one.

(c) As a result of the arrests and investigation, the greater part of the amount involved has been recovered.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : वह प्रश्नर देखा गया है कि को-ऑपरेटिव बैंक में ऐसे

बहुत से गॉल-माल हो रहे हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतावेंगे कि क्या गवर्नमेंट इस बारे में विचार करने के लिये कोई कमेटी बिठाने की सोच रही है ताकि इस किस्म की बातें फ्राइन्दा न हो सकें ?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: We take steps to see that such things do not happen, and when they do happen, we take immediate measures.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : प्रश्नर यह देखा गया है कि ये को-ऑपरेटिव सोसायटीज ऐसे बिज़नेस करती हैं, जिन में घाटा ही घाटा होता है और उसमें डायरेक्टर्स का भी हिस्सा होता है। इसलिये आवश्यकता यह जान पड़ती है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द एक ऐसी योजना बनाये, जिसके द्वारा फ्राइन्दा ऐसी बातों को रोका जा सके। क्या गवर्नमेंट इस पर भी विचार करेगी ?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: In this particular case there was no loss. The co-operative bank has made profit. It is one of defalcation, and this defalcation has been found out and the person has been apprehended.

श्री कुकम चन्द कश्यप : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में इस प्रकार के कितने को-ऑपरेटिव बैंक हैं जिनके बारे में उनको घोटाले की सूचना मिली है। उनके सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को ऐरेस्ट किया गया और कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये। उन्होंने कहा है कि कुछ धनराशि बसूल की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी धनराशि बसूल की गई है।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: The defalcation was to the extent of Rs. 1,09,200. We have recovered so far Rs. 1,07,311. So, only a small amount has to be recovered. The person has been apprehended.

श्री एचि रोथ : उस व्यक्ति का नाम क्या है ?